



गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 16

अंक : 003

दि. 03.05.2026,

रविवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

बदलते भारत की नई तस्वीर: विश्वविद्यालय में ‘मोदी तत्व’ से नेतृत्व की पढ़ाई

(जीएनएस)। वडोदरा। भारत के शैक्षणिक परिदृश्य में एक नया अध्याय जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो यह संकेत देता है कि देश केवल विकास के आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि विचार और अध्ययन के स्तर पर भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। गुजरात के वडोदरा स्थित Maharaja Sayajirao University of Baroda ने अपने समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में एक नया मॉड्यूल जोड़कर इस बदलाव को एक ठोस रूप दिया है। इस मॉड्यूल का नाम है ‘मोदी तत्व’, जिसके माध्यम से छात्रों को Narendra Modi के नेतृत्व, उनके निर्णयों और समाज पर उनके प्रभाव का अध्ययन करवा जाएगा। यह पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रयोग है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि आधुनिक भारत अपने समकालीन नेताओं और उनके प्रभाव को अकादमिक विमर्श का हिस्सा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

इस नए पाठ्यक्रम को ‘देशभक्ति का समाजशास्त्र’ शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसे एमए समाजशास्त्र के दो वर्षीय कार्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख डॉ. वीरेंद्र सिंह के अनुसार, इस कोर्स का उद्देश्य केवल

किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व शैली, सामाजिक प्रभाव और नीतिगत निर्णयों का वैज्ञानिक और निष्पक्ष विश्लेषण करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रभावशाली नेता को समझने के लिए उसे अकादमिक दृष्टि से परखना जरूरी होता है, चाहे वह किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो। इस अध्ययन में समाजशास्त्र के प्रसिद्ध चिंतक Max Weber के ‘करिश्माई नेतृत्व’ के सिद्धांत को आधार बनाया गया है। वेबर के अनुसार, करिश्माई नेता वह होता है जो अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं और असाधारण व्यक्तित्व के कारण लोगों को प्रभावित करता है और लंबे समय तक उनके बीच अपनी स्वीकार्यता बनाए रखता है। इतिहास में Mahatma Gandhi और Martin Luther King Jr. को ऐसे नेताओं के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। इसी संदर्भ में अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को भी एक अध्ययन के रूप में शामिल किया जा रहा है, ताकि यह समझा जा सके कि उनकी लोकप्रियता के पीछे कौन से सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक काम कर रहे हैं।

यह पाठ्यक्रम केवल सिद्धांतों तक सीमित



नहीं रहेगा, बल्कि इसमें व्यावहारिक पहलुओं पर भी गहराई से चर्चा की जाएगी। छात्रों को नोटबंदी, डिजिटल इंडिया अभियान, फास्टेग प्रणाली और जल शक्ति मंत्रालय जैसे प्रमुख नीतिगत निर्णयों का विश्लेषण कराया जाएगा। इन नीतियों के माध्यम से यह समझने की कोशिश की जाएगी कि किस प्रकार सरकार ने आम नागरिकों के जीवन में बदलाव लाने

का प्रयास किया और इन प्रयासों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। यह अध्ययन छात्रों को यह भी सिखाएगा कि नीतियां केवल कागज पर नहीं होतीं, बल्कि उनका वास्तविक असर लोगों के जीवन में किस तरह दिखाई देता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में Rashtriya Swayamsevak Sangh के इतिहास और सामाजिक योगदान को भी शामिल



किया गया है। डॉ. वीरेंद्र सिंह के अनुसार, जब छात्र नीति आयोग से जुड़े प्रोजेक्ट्स के तहत गांवों में सर्वेक्षण कर रहे थे, तब उन्होंने पर नहीं होतीं, बल्कि उनका वास्तविक असर लोगों के जीवन में किस तरह दिखाई देता है। इस अनुभव के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि इस संगठन के सामाजिक प्रभाव का भी अध्ययन किया जाना

चाहिए, ताकि छात्रों को जमीनी स्तर पर हो रहे बदलावों की बेहतर समझ मिल सके। इस कोर्स में मीडिया, डिजिटल राष्ट्रवाद, नागरिकता, असहमति, वैश्वीकरण और पहचान की राजनीति जैसे समकालीन विषयों को भी शामिल किया गया है। यह दर्शाता है कि पाठ्यक्रम को केवल एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि

इसे व्यापक सामाजिक संदर्भ में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को यह समझाना है कि आज के दौर में राजनीति, समाज और तकनीक किस तरह एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनका संयुक्त प्रभाव किस प्रकार देश की दिशा तय करता है। हालांकि इस पहल को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आना स्वाभाविक है। कुछ लोग इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक प्रयोग मान रहे हैं, जहां समकालीन नेतृत्व को अकादमिक अध्ययन का हिस्सा बनाया जा रहा है, वहीं कुछ लोग इसे एक विशेष विचारधारा को बढ़ावा देने के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है, जिससे छात्र किसी भी विषय को गहराई से समझ सकें।

यह पहल इस बात का भी संकेत है कि भारत की शिक्षा प्रणाली धीरे-धीरे बदल रही है। अब केवल पारंपरिक विषयों तक सीमित रहने के बजाय, विश्वविद्यालय समकालीन मुद्दों और वर्तमान नेतृत्व को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। इससे छात्रों को न केवल

सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है, बल्कि वे वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों को भी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह बदलाव भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है, जहां शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के साथ जुड़ी हुई होगी। इस पूरे घटनाक्रम को अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है—चाहे वह राजनीति हो, समाज हो या शिक्षा। ‘मोदी तत्व’ जैसे पाठ्यक्रम इसी परिवर्तन का प्रतीक हैं, जो यह दिखाते हैं कि देश अपने वर्तमान को समझने और भविष्य को आकार देने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि यह पहल केवल एक पाठ्यक्रम जोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि यह उस सोच का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें शिक्षा को समय के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यह छात्रों को न केवल ज्ञान देगा, बल्कि उन्हें सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता भी प्रदान करेगा। यही वह बदलाव है, जो एक राष्ट्र को आगे बढ़ने की दिशा देता है और उसे एक नई पहचान प्रदान करता है।

मतगणना पर सियासी संग्राम: सिब्बल की मांग, आयोग की सफाई और कोर्ट की मुहर

(जीएनएस)। कोलकाता / नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमा गया है, जहां पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं। वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री Kapil Sibal ने मतगणना प्रक्रिया को लेकर अहम बयान देते हुए कहा है कि हर टेबल पर राज्य सरकार के एक कर्मचारी की मौजूदगी अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि सभी राजनीतिक दलों को बराबरी का भरोसा मिल सके। उनके इस बयान ने चुनावी बहस को और तेज कर दिया है, खासकर उस समय जब राज्य में मतगणना की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। सिब्बल का तर्क साफ है कि यदि केवल केंद्रीय या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी ही मतगणना में प्रमुख भूमिका निभाएंगे, तो कुछ राजनीतिक दलों के मन में पक्षपात की आशंका बनी रह सकती है। उनका मानना है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की समान भागीदारी से संतुलन बनेगा और प्रक्रिया पर विश्वास और मजबूत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब मतगणना की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड होती है और कई स्तरों पर निगरानी रहती है, तो पारदर्शिता



सुनिश्चित करना और भी आसान हो जाता है। ऐसे में सभी पक्षों की भागीदारी एक सकारात्मक कदम हो सकती है। इस मुद्दे ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब यह मामला Supreme Court of India तक पहुंच गया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मतगणना के दौरान कर्मचारियों की नियुक्ति करना Election Commission of India का अधिकार क्षेत्र है और इसमें किसी अतिरिक्त निर्देश की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने आयोग के सफ़ुल्ल को सही ठहराते हुए यह भी कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया कि आयोग अपने निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इस पूरे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने

भी अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा है कि मतगणना पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। आयोग के अनुसार, गिनती के दौरान केंद्रीय और राज्य—दोनों प्रकार के कर्मचारियों की मौजूदगी रहेगी, जिससे किसी भी प्रकार के असंतुलन की संभावना नहीं रहेगी। आयोग ने यह भी भरोसा दिलाया है कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल और निगरानी व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाएगा, ताकि हर वोट की गिनती सही तरीके से हो सके। वहीं, जमीन पर हालात भी कुछ अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके के हसिमनगर गांव क्षेत्र में सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें मतगणना के बाद जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिससे उनके बीच डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। यह घटना बताती है कि चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन को भी सीधे प्रभावित करता है। ऐसे में मतगणना

की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा विवाद केवल कर्मचारियों की तैनाती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक अविश्वास की भावना भी छिपी हुई है। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर दल चाहता है कि उसे पूरी निष्पक्षता मिले, लेकिन जब भरोसे की कमी होती है, तो छोटे-छोटे मुद्दे भी बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं। यही कारण है कि सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील इस मुद्दे को उठाकर एक व्यापक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, चुनाव आयोग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक संवैधानिक संस्था के रूप में उसका दायित्व है कि वह सभी पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखे और यह सुनिश्चित करे कि प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का संदेह न रहे। आयोग द्वारा दिए गए आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से यह संकेत जरूर मिलता है कि संस्थागत स्तर पर प्रक्रिया को लेकर विश्वास बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।

नई दिशा में बढ़ते कदम: भारत—इक्वाडोर साझेदारी से खुलेंगे वैश्विक अवसरों के द्वार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक कूटनीति के बदलते परिदृश्य में भारत लगातार अपने संबंधों को नए क्षेत्रों और नए साझेदारों तक विस्तार दे रहा है। इसी क्रम में India और Ecuador के बीच हालिया उच्च स्तरीय संपर्क ने द्विपक्षीय रिश्तों को एक नई ऊर्जा दी है। इक्वाडोर की विदेश मंत्री Gabriela Sommerfeld की भारत यात्रा को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसने व्यापार, स्वास्थ्य, तकनीक और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खोल दिए हैं। यह दौरा केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें दोनों देशों ने ठोस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सहमति भी जताई। इस यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा जोर आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर रहा। दोनों देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके बीच व्यापार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिन्हें अभी पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया गया है। व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई, जिससे भविष्य में द्विपक्षीय व्यापार को गति मिल सके। इक्वाडोर ने विशेष रूप से अपने प्रमुख निर्यात उत्पादों—केला, कोको और झींगा—के लिए भारतीय बाजार में अधिक अवसरों की तलाश पर जोर दिया। भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार में इन उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह कदम इक्वाडोर के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरी ओर, भारत ने भी इक्वाडोर के ऊर्जा और खनन क्षेत्रों में निवेश की अपनी रूचि जाहिर की है। यह संकेत देता है कि भारत



केवल आयात-निर्यात तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से इस साझेदारी को और गहरा बनाना चाहता है। ऊर्जा और खनन जैसे क्षेत्र किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ होते हैं, और इनमें निवेश से दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग की नींव और मजबूत होगी। स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र इस दौर का सबसे अहम पहलू बनकर उभरा। भारत ने इक्वाडोर को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जैनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। भारत को दुनिया की ‘फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड’ कहा जाता है, और उसकी दवाइयों की गुणवत्ता और किफायती कीमतों ने वैश्विक स्तर पर उसे एक मजबूत पहचान दिलाई है। ऐसे में इक्वाडोर के लिए यह सहयोग उसकी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में एक बड़ा सहारा बन सकता है। इसके साथ ही, दोनों देशों ने जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में संयुक्त प्रयासों की संभावनाओं पर भी चर्चा की, जो भविष्य में नवाचार और शोध को नई दिशा दे

सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी यह साझेदारी नए आयाम खूली नजर आ रही है। भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के अनुभव को साझा करने की पेशकश की है, जिसने देश में डिजिटल क्रांति को गति दी है। डिजिटल भुगतान, पहचान प्रणाली और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण में भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे अन्य देशों के लिए एक मॉडल बन चुकी हैं। इक्वाडोर ने इन अनुभवों से सीखने और अपनी प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रणालियों को आधुनिक बनाने की इच्छा जताई है। यह सहयोग न केवल तकनीकी विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि प्रशासनिक दक्षता को भी बेहतर बनाएगा। इस दौर का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। आज के दौर में, जब पर्यावरणीय चुनौतियां पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत और इक्वाडोर का इस दिशा में एक साथ काम करने का

संकल्प यह दर्शाता है कि वे केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी उतना ही महत्व देते हैं। यह दौरा एक व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा भी है, जिसके तहत भारत लैटिन अमेरिका क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। इक्वाडोर जैसे देशों के साथ बढ़ते संबंध न केवल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह भारत की वैश्विक कूटनीतिक पहुंच को भी विस्तार देते हैं। यह साझेदारी इस बात का संकेत है कि भारत अब पारंपरिक सहयोगियों से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में भी अपने प्रभाव को स्थापित कर रहा है। कुल मिलाकर, भारत और इक्वाडोर के बीच यह बढ़ती साझेदारी केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक ठोस और दूरगामी सहयोग का आधार बनती जा रही है। व्यापार, स्वास्थ्य, तकनीक और पर्यावरण जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग के ये प्रयास आने वाले समय में दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं।



गरवी गुजरात

हिन्दी

JioTV

CHENNAL NO. 2002

Jio FIBER

Jio tv+

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba TV

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Roku

Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये



संपादकीय

शोर का न ओर-छोर

यूं तो हाल के वर्षों में आम भारतीय की अभिव्यक्ति में तलछी व शोर का ग्राफ तेज हुआ है। अभिव्यक्ति का मुखर होना अच्छा है लेकिन उसका तलछ होना, किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैसे हमारे परिवेश में लगातार बढ़ता शोर झेलना हमारी नियति हो चला है। सड़कों पर वाहनों के शोर, नये दौरे के कर्कश संगीत से लेकर राजनीतिक विमर्श में होने वाले शोरगुल वाले संवाद से लेकर तमाम ऐसा कुछ घट रहा है, जो हमारी परेशानी का सबब बन रहा है। यूं तो कोई प्रमाणिक राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक शोध व्यापक रूप में हमारे सामने तो नहीं आए हैं जो ठीक-ठीक बताएं कि ध्वनि प्रदूषण हमारी सेहत पर कितना घातक असर डाल रहा है। लेकिन गाहे-बगाहे सामने आए आंकड़े इस बात की पुष्टि जरूर करते हैं कि लगातार बढ़ता शोर हमारी सेहत बिगाड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद इसे रोकने के लिए उचित निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई और दंड के प्रावधान लागू होते नजर नहीं आते हैं। लेकिन विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्ष बता रहे हैं देश के महानगरों से लेकर कस्बों तक हमारे परिवेश का शोर तय मानकों से कहीं अधिक है। जाहिरा तौर ये शोर हमारी सेहत को गहरे तक प्रभावित कर रहा है। जिससे न केवल हमारी श्रवण शक्ति कमजोर हो रही है बल्कि नींद में कमी, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप के अलावा हृदय रोग तक का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन इस दिशा में कागजों में तो लुभावनी योजनाएं तो बनायी जाती हैं लेकिन जमीनी हकीकत बदलती नजर नहीं आती। यह सुखद है कि पिछले दिनों देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस दिशा में नई पहल शुरू की गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया आरंभ की है। दावा किया जा रहा है कि प्रदूषण के स्रोतों को कायादे से निगरानी होगी। इसके अलावा समयबद्ध ढंग से कार्रवाई होगी। साथ ही जुर्माना भी अनिवार्य रूप से वसूला जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बतानाएगा कि अच्छी योजना कितनी जमीनी हकीकत बनती है।

लेकिन सवाल यह है कि जब देश में पहले से शोर नियंत्रण के कानून मौजूद हैं और हमारी अदालतें भी समय-समय पर हमारे नीति निवेदाओं को आगाह करती ही रहती हैं, तो फिर सूरत क्यों नहीं बदलती। आखिर इन नियम-कानूनों के क्रियान्वयन में कहां खोट हो जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम, 2000 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों, निर्माण कार्यों और उद्योगों में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों, वाहनो के हार्न आदि अन्य स्रोतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। ताकि लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा हो पा। उल्लेखनीय है कि ये प्रावधान दिन व रात के लिये अलग-अलग हैं। जिसके अंतर्गत रात के दस बजे से लेकर सुबह छह बजे के मध्य लाउडस्पीकर लगाना मना है। यदि अपरिहार्य कारणों से कुछ अधिक समय के लिये इसका उपयोग किया भी जाना है तो संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन कानूनों का जमकर उल्लंघन करना शान समझा जाता है। जाहिर बात है कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी इसकी निगरानी और रोकने के लिये होती है वे अपने दायित्वों को भलीभांति निर्वहन नहीं करते हैं। सख्ती के अभाव में लोग इसे न्यू नॉर्मल बना देते हैं। विडंबना यह है कि छोटे शहरों व कस्बों ही नहीं, बड़े शहरों में भी ध्वनि का स्तर नापने वाले यंत्र या तो लगे नहीं हैं, या फिर वे ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। यही वजह है कि देश के सामने वह तस्वीर नहीं उभरती कि देश में ध्वनि प्रदूषण का स्तर कितना घातक हो चला है। दादी-नानी कहें कि देश में जब प्रमाणिक डाटा ही उपलब्ध नहीं है तो उसके निदान और उसके पड़ने वाले घातक प्रभावों की हकीकत कैसे सामने आएगी। वास्तव में गैर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। यदि वे फिर भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

अभियान

पीपल की छांव का सच: डर, परंपरा और विज्ञान के बीच छिपी जीवन की समझ

भारतीय गांवों की रातों में एक अलग ही जादू होता है—खुला आसमान, टंडी हवा, दूर तक पसरा सन्नाटा और बीच-बीच में पेड़ों की सरसराहट। ऐसे वातावरण में लोग अक्सर पेड़ों के नीचे बैठकर सुकून ढूँढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही बात Peepal Tree की आती है, दादी-नानी की आवाज़ तुरंत गुंज उठती है—“पीपल के नीचे मत बैठो, भूत पकड़ लेगा।” यह वाक्य सुनते ही मन में एक रहस्य और हल्का सा डर पैदा होता है। लेकिन क्या यह केवल अंधविश्वास है, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? जब हम इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह चेतावनी केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा, प्रकृति की समझ और सामाजिक संतुलन बनाए रखने का एक तरीका थी।

भारतीय संस्कृति में पीपल का पेड़ केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि इसे जीवंत ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें Vishnu का वास होता है, और यही कारण है कि इसे अत्यंत पवित्र समझा जाता है। इसके

अलावा, Gautama Buddha को ज्ञान की प्राप्ति भी इसी वृक्ष के नीचे हुई थी, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। लोग पीपल की पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और उसे जीवनदायिनी शक्ति का स्रोत मानते हैं। यह श्रद्धा केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है।

लेकिन जहां एक ओर पीपल को पूजनीय माना गया, वहीं दूसरी ओर उससे जुड़ी कुछ सावधानियां भी कहा गया कि शाम के बाद पीपल के पास नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। यह सुनने में भले ही रहस्यमयी लगे, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखना था। पुराने समय में जब बिजली नहीं थी, अंधेरा घना होता था और जंगल या सुनसान स्थानों में खतरे की संभावना अधिक होती थी, तब बच्चों और महिलाओं को रात में बाहर जाने से रोकने के लिए इस तरह की कहानियां बनाई गईं। “भूत पकड़ लेगा” एक प्रतीकात्मक भाषा थी, जो सीधे-सीधे खतरों को समझाने का एक

सरल तरीका थी।

अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो यह चेतावनी और भी स्पष्ट हो जाती है। दिन के समय पेड़-पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध और ताजा बना रहता है। पीपल का पेड़ इस प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां बड़ी और सक्रिय होती हैं, जो अधिक मात्रा में गैसों का आदान-प्रदान करती हैं। यही कारण है कि दिन के समय पीपल के नीचे बैठना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है।

लेकिन रात में स्थिति बदल जाती है। सूर्य के प्रकाश के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद जाती है और पेड़ श्वसन प्रक्रिया के तहत ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया सभी पेड़ों में होती है, लेकिन बड़ और घने पेड़ों के नीचे इसका प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक रात में पीपल के नीचे बैठा रहे, तो

उसे घुटन या बेचैनी महसूस हो सकती है, खासकर जब हवा का प्रवाह कम हो। यही कारण है कि बुजुर्ग रात में इसके नीचे बैठने से मना करते थे। इसके अलावा, पीपल के पेड़ के नीचे रात के समय मच्छर, कीट-पतंगे और अन्य छोटे जीव अधिक सक्रिय हो जाते हैं। यह न केवल असुविधाजनक होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। पुराने समय में मेलरिया, डेंगू जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी सीमित थी, लेकिन अनुभव के आधार पर लोग जानते थे कि मच्छरों से दूरी बनाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने इसे एक सरल चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि लोग आजाने में खतरों में न पड़ें।

पीपल के पेड़ का एक और पहलू है—उसका स्थान। यह पेड़ अक्सर पुराने मंदिरों, श्मशान घाटों या गांव के किनारों पर पाया जाता है, जहां वातावरण स्वाभाविक रूप से शांत और थोड़ा रहस्यमयी होता है। ऐसे स्थानों पर रात के समय अकेले बैठना मनोवैज्ञानिक रूप से भी अरहजात पैदा कर सकता है। हल्की सी आवाज़ भी डर का कारण बन सकती है, और यही

डर धीरे-धीरे “भूत-प्रेत” की कहानियों का रूप ले लेता है। इस तरह, यह चेतावनी केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक सुरक्षा से भी जुड़ी थी। भारतीय परंपराओं की खास बात यह है कि वे प्रकृति के साथ गहरे जुड़ी हुई हैं। हर नियम, हर मान्यता के पीछे कोई न कोई व्यावहारिक कारण होता है। दादी-नानी की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती थीं, बल्कि हमें जीवन के अनुभवों का सार होती थीं। उन्होंने हमें विज्ञान की भाषा का उपयोग नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों में विज्ञान की सच्चाई जरूर छिपी होती थी। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा, जिससे समाज सुरक्षित और संतुलित बना रहा। आज के समय में, जब हम हर बात को तर्क और प्रमाण के आधार पर परखते हैं, तब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं होतीं। उनमें अनुभव, पर्यावरण और सामाजिक संरचना का गहरा ज्ञान होता है। अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें, तो हमें पता चलता है कि वे हमारे जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए बनाई गईं

थीं। पीपल के पेड़ से जुड़ी यह चेतावनी हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हर पेड़, हर पौधा हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनके साथ व्यवहार करने के कुछ नियम होते हैं। दिन में जो पेड़ हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देता है, वही रात में अलग व्यवहार करता है, जो हमें याद दिलाता है कि हमें एक बेहतर, अधिक संतुलित और अधिक अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। यही उस दीपक का असली प्रकाश है, जो बाहर से छोट दिखता है, लेकिन भीतर से पूरे जीवन को रोशन कर देता है।

धर्म शासित ईरान की सामरिक-आक्रामक तैयारी व बढ़ती सैन्य क्षमता गैर इस्लामिक देशों के लिए नसीहत है, कैसे?

“

मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी का संयुक्त मॉडल ही ईरानी सफलता का सूत्र है, क्योंकि ईरान ने केवल अपनी सेना पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय नेटवर्क तैयार किया—हिजबुल्लाह, हूती और अन्य सहयोगी समूहों के माध्यम से उसने बहु-स्तरीय दबाव बनाया। यह “Hybrid Warfare” का आधुनिक मॉडल है।

प्रेरणा

विवेक का प्रकाश: जीवन को दिशा देता ज्ञान का दीपक

एक शांत विश्वविद्यालय कक्ष में बैठे विद्यार्थियों के बीच जब Sarvepalli Radhakrishnan अपने गहन विचारों के साथ अध्यापन कर रहे थे, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि उस दिन एक साधारण सा प्रश्न जीवन का गूढ़ सत्य खोल देगा। कक्षा में दर्शनशास्त्र का पाठ चल रहा था, विषय गंभीर था, और वातावरण अनुशासन से भरा हुआ। तभी एक छात्र ने साहस जुटाकर प्रश्न किया—“सर, दर्शन पढ़ने से जीवन में क्या बदलेगा? पेट तो इससे नहीं भरता।” यह प्रश्न केवल उस छात्र का नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति का था जो जीवन को केवल भौतिक आवश्यकताओं के चक्कर में घुमा रहा हो। प्रश्न सुनते ही कक्षा में सन्नाट छा गया। सभी की निगाहें राधाकृष्णन की ओर टिक गईं, मानो वे किसी गहरे उतर की प्रतीक्षा कर रहे हों। राधाकृष्णन ने कुछ क्षणों तक मौन साधा। उनके चेहरे पर न कोई असहजता थी, न ही कोई त्वरित प्रतिक्रिया। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा—“तुम सही कह रहे हो, ज्ञान पेट नहीं भरता।” यह सुनकर छात्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसे अपने प्रश्न का समर्थन मिल गया हो। लेकिन अगले ही क्षण राधाकृष्णन ने जो कहा, उसने उस मुस्कान को गंभीरता में बदल दिया। उन्होंने कहा—“लेकिन पेट भरने के लिए काम चाहिए, और सही काम चुनने के लिए विवेक चाहिए। दर्शन वही विवेक देता है।” यह उतर केवल तर्क नहीं था, बल्कि जीवन का अनुभव था, जो एक शिक्षक अपने शिष्य को यौप्य रहा था।

फिर उन्होंने मेज़ पर रखे दीपक की ओर इशारा किया। दीपक की लौ स्थिर थी, शांत थी, लेकिन उसमें

एक अद्भुत शक्ति थी—अंधकार को दूर करने की। राधाकृष्णन ने कहा—“दीपक भोजन नहीं बनाता, लेकिन बिना उसके रसोई अंधेरे में रहती है। उसी तरह ज्ञान जीवन का बोझ नहीं उठाता, पर वह दिशा देता है।” यह उदाहरण इतना सरल था कि हर छात्र उसे समझ सका, और इतना गहरा था कि वह जीवन पर याद रहने वाला था। उस क्षण कक्षा में केवल एक उतर नहीं दिया गया, बल्कि एक दृष्टिकोण दिया गया—हम अक्सर शिक्षा को केवल रोजगार के संदर्भ में आंकते हैं। हम यह सोचते हैं कि पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छी नौकरी प्राप्त करना है, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोजगार आवश्यक है। लेकिन क्या जीवन केवल आवश्यकताओं का नाम है? क्या मनुष्य का अस्तित्व केवल पेट भरने तक सीमित है? यही वह प्रश्न है जिसे दर्शन हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि सार्थक रूप से जीना है।

जब हम विवेक की बात करते हैं, तो उसका अर्थ केवल सही और गलत का ज्ञान नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों में संतुलन बनाना, निर्णयों में दूरदृष्टि रखना, और अपने कर्मों के परिणामों को समझना भी होता है। विवेक वह आंतरिक प्रकाश है जो हमें अंधेरे में भी सही रास्ता दिखाता है। यह वही शक्ति है जो एक व्यक्ति को भीड़ से अलग बनाती है। बिना विवेक के ज्ञान भी अंधूरा है, क्योंकि वह केवल सूचना बनकर रह जाता

है। लेकिन जब ज्ञान के साथ विवेक जुड़ता है, तब वह जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। आज के समय में, जब दुनिया तेजी से बदल रही है, जब तकनीक और प्रतियोगी ने जीवन को जटिल बना दिया है, तब विवेक की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। हम ज्ञान की महासागर में जी रहे हैं, लेकिन सही जानकारी कभी अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाती है। ऐसे में दर्शन का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि वह हमें सोचने की क्षमता देता है। वह हमें यह सिखाता है कि हर निर्णय केवल तात्कालिक लाभ के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि उसके दीर्घकालिक प्रभावों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

राधाकृष्णन का यह संदेश केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि आंतरिक संतुलन और संतोष से भी जुड़ी होती है। एक व्यक्ति जिसके पास विवेक का प्रकाश है, वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है, और वही उसे असाधारण बनाता है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करती है। शिक्षा केवल जानकारी का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है—स्वयं को समझने की, दुनिया को समझने की, और दोनों के बीच संतुलन बनाने की। जब हम इस दृष्टिकोण से शिक्षा को देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हर विषय, चाहे वह दर्शन हो, विज्ञान हो या कला, हमें कुछ न कुछ सिखाता

है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है।

छात्र, जिसने यह प्रश्न पूछा था, शायद उस दिन केवल एक उत्तर लेकर नहीं गया, बल्कि एक नई सोच लेकर गया। उसकी आंखें झुंक गईं, लेकिन वह झुकाना हार का नहीं, बल्कि समझ का था। उसने यह महसूस किया कि जीवन को केवल एक आयाम में देखना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन उसने ज्ञान कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजी-रोटी कमाना नहीं, बल्कि सही रास्ता चुनने की क्षमता विकसित करना है। जब हमारे जीवन का दीपक जलता है, तब हम जीवन की कठिनतायें से डरते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। हम परिस्थितियों के शिकार नहीं बनते, बल्कि उन्हें अपने अनुसार ढालते हैं। यही वह शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हमारे पास सही दृष्टिकोण है, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।

अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि ज्ञान का दीपक भले ही हमारे लिए भोजन न बना सके, लेकिन वह हमें उस रसोई तक पहुंचने का रास्ता जरूर दिखाता है, जहां हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने और संवरने के लिए है। और जब हम इस समझ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारा हर कदम हमें एक बेहतर, अधिक संतुलित और अधिक अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। यही उस दीपक का असली प्रकाश है, जो बाहर से छोट दिखता है, लेकिन भीतर से पूरे जीवन को रोशन कर देता है।



करोड़ की एयर डिफेंस प्रणाली को सस्ते ड्रोन झुंड (swarm) से भी चुनौती दी जा सकती है। इसलिए आज अमेरिका तक स्वीकार कर रहा है कि महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों के मुकाबले सस्ते ड्रोन “Cost Imbalance” पैदा कर रहे हैं। तीसरा, युद्ध केवल हथियार नहीं, बल्कि विरोधी की आर्थिक, सैन्य और मनोवैज्ञानिक क्षमता को धकाना रहा। यह आधुनिक युद्ध की नई वास्तविकता है—“हर युद्ध Blitzkrieg नहीं होता; कई युद्ध विरोधी को थकाकर जीते जाते हैं।”

चौथा, कमांड सिस्टम का बैकअप अत्यंत जरूरी होता है, ताकि भारी हमलों और शीर्ष कमांडरों के मारे जाने के बावजूद ईरान ने काम लागू वाले ड्रोन को “रणनीतिक हथियार” बना दिया। उसने दिखाया कि हजारों

विकेंद्रीकृत कमांड संरचना तैयार कर रखी थी। यह हर राष्ट्र के लिए बड़ा संदेश है कि—“युद्ध में नेतृत्व का विकल्प पहले से तैयार होना चाहिए।” पांचवां, मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी का संयुक्त मॉडल ही ईरानी सफलता का सूत्र है, क्योंकि ईरान ने केवल अपनी सेना पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय नेटवर्क तैयार किया—हिजबुल्लाह, हूती और अन्य सहयोगी समूहों के माध्यम से उसने बहु-स्तरीय दबाव बनाया। यह “Hybrid Warfare” का आधुनिक मॉडल है। छठा, समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की शक्ति विकसित करके आक्रमणकारियों को तोड़ना ईरानी दूरदर्शिता का ही तकाजा है, क्योंकि होर्मुज जलदमरूमध्य पर ईरान का प्रभाव पूरी दुनिया की ऊर्जी सुरक्षा को प्रभावित करता है। इसी कारण अमेरिका और पश्चिम लगातार उस क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाते रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है—“पूगोले थी उतना ही बड़ा हथियार है जितना मिसाइल।”

सातवां, तकनीकी युद्ध में सस्ता हथियार भी निर्णायक होता है, यह ईरान ने सबित कर दिया है। ईरान ने दिखाया कि हर युद्ध अत्याधुनिक स्टील फाइटर से नहीं जीता जाता। कभी-कभी सस्ती, तेज और बड़ी

संख्या में उपलब्ध तकनीक अधिक प्रभावी होती है।

निष्कर्षतः ईरान की तैयारी हर इस्लामिक दुनिया को यह सिखाती है कि आधुनिक युद्ध केवल गुणगुण बम या महंगे लड़ाकू विमानों से नहीं लड़े जाते। आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, ड्रोन तकनीक, मिसाइल क्षमता, साइबर-रणनीति, वैकल्पिक नेतृत्व और मनोवैज्ञानिक युद्ध—ये सब मिलकर किसी राष्ट्र को सामरिक शक्ति बनाते हैं। इसीलिए आज अमेरिका, इजराइल, रूस, चीन और भारत समेत दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां भी “ईरानी मॉडल” का गंभीर अध्ययन कर रही हैं।

एक बात और, ईरान के सामरिक मॉडल से भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि केवल पारंपरिक सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं होती; दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए “बहुस्तरीय राष्ट्रीय प्रतिरोध क्षमता” विकसित करनी पड़ती है। विशेषकर तब, जब भारत को दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, कट्टरपंथ और चीन-पाकिस्तान जैसे सामरिक गठबंधनों का सामना करना पड़ रहा हो। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि “इस्लामिक देश” एक समान इकाई नहीं हैं। भारत के कई इस्लामी देशों—जैसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, इंडोनेशिया और कतर—से मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। भारत की मुख्य सुरक्षा चुनौती कुछ कट्टरपंथी नेटवर्क, आतंकवादी संरचनाओं और शत्रुतापूर्ण राज्य-नीतियों से रही है, न कि समूर्ण इस्लामी विश्व से।

भारत के लिए प्रमुख सबक इस प्रकार हैं— पहला, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन ही निर्णायक सुरक्षा: ईरान ने प्रतिबंधों के बावजूद अपने ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तंत्र विकसित किए। भारत के लिए इसका अर्थ है कि विदेशी हथियारों पर अत्यधिक निर्भरता घटानी होगी। “आत्मनिर्भर भारत” को केवल नारा नहीं, बल्कि युद्धकालीन औद्योगिक क्षमता बनाना होगा।

दूसरा, सस्ते ड्रोन बनाम महंगी सुरक्षा: ईरान ने दिखाया कि कम लागत वाले ड्रोन भी महंगी एयर डिफेंस प्रणाली को चुनौती दे सकते हैं। भारत को सीमा सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी अभियानों और समुद्री

निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर स्वदेशी ड्रोन नेटवर्क बनाना होगा। तीसरा, “मेजेक डिफेंस” मॉडल: ईरान की विकेंद्रीकृत सैन्य संरचना—जहां शीर्ष नेतृत्व या महंगे लड़ाकू विमानों से नहीं लड़े जाते। आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, ड्रोन तकनीक, मिसाइल क्षमता, साइबर-रणनीति, वैकल्पिक नेतृत्व और मनोवैज्ञानिक युद्ध—ये सब बहुस्तरीय कमांड संरचना विकसित करनी होगी जो अचानक हमले में भी सक्रिय रहे।

चौथा, केवल सीमा नहीं, “मनोवैज्ञानिक युद्ध” भी: आतंकवादी संघर्ष अब केवल बंदूक और मिसाइल का नहीं, बल्कि सूचना और नैटिव का भी है। भारत को फेक न्यूज़, साइबर-प्रोपेगंडा और धार्मिक कट्टरता आधारित डिजिटल अभियानों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा ढांचा मजबूत करना होगा। पांचवां, लंबी लड़ाई की तैयारी: ईरान ने दिखाया कि “War of Attrition” यानी विरोधी को धीरे-धीरे थकाना भी रणनीति हो सकती है। भारत को सीमित अवधि के युद्ध की सोच से आगे जाकर लंबे संघर्ष, आपूर्ति शृंखला और गोला-बारूद भंडारण की तैयारी करनी होगी।

छठा, ऊर्जा सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा है: यदि पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध होता है, तो भारत की तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसलिए सामरिक तेल भंडार, वैकल्पिक ऊर्जा और समुद्री मार्ग सुरक्षा भारत के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सातवां, “संयुक्त युद्ध” की तैयारी: आज युद्ध भूमि, समुद्र और आकाश तक सीमित नहीं है; साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र भी युद्धक्षेत्र बन चुके हैं। भारत को एिएए कमांड, AI आधारित निगरानी और संयुक्त सैन्य संचालन को तेज करना होगा।

आठवां, राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ी सुरक्षा: ईरान के उदाहरण से यह भी स्पष्ट हुआ कि बाहरी दबाव के समय आंतरिक सामाजिक एकता निर्णायक होती है। भारत जैसे विविधातुण राष्ट्र में सांप्रदायिक विभाजन, राजनैतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक अविश्वास राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं।

ट्रंप–मर्ज़ टकराव: अमेरिका-जर्मनी रिश्तों में बढ़ती खाई, वैश्विक संतुलन पर असर

अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां शब्दों की जंग के पीछे रणनीतिक संघर्ष गहराता जा रहा है। इस बार केंद्र में हैं Donald Trump और Friedrich Merz, जिनके बीच हालिया बयानबाजी ने अमेरिका और जर्मनी के संबंधों में नई दरार पैदा कर दी है। ट्रंप, जो अक्सर वैश्विक नेताओं पर तीखे हमले करने के लिए जाने जाते हैं, ने मर्ज़ को सीधे तौर पर निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और ईरान जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में दखल देने से बचना चाहिए। यह बयान उस समय आया जब दोनों देशों के बीच ईरान संकट, रूस-यूक्रेन युद्ध और नाटो सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं।

ट्रंप ने अपने आरोपों में यह भी कहा कि मर्ज़ रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने में पूरी तरह विफल रहे हैं और जर्मनी के भीतर बढ़ते आतुरजन संकट तथा ऊर्जा समस्याओं को संभालने में भी कमजोर साबित हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह संकेत भी दिया कि ईरान के परमाणु खतरों से निपटने के लिए अमेरिका जो कदम उठा रहा है, उसमें जर्मनी को बाधा नहीं बनना चाहिए।

यह टिप्पणी केवल आलोचना नहीं, बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। इस विवाद की शुरुआत तब और तेज हो गई जब मर्ज़ ने अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईरान के साथ चल रही बातचीत में अमेरिका की स्थिति कमजोर और अपमानजनक दिख रही है। तथा उसके पास युद्ध से बाहर निकलने के कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। मर्ज़ की इस टिप्पणी ने ट्रंप को नाजिर कर दिया और उन्होंने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया दी, जिससे दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक तकराव खुलकर सामने आ गया।

तनाव उस समय और बढ़ गया जब ट्रंप ने जर्मनी में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने की संभावना जताई। वर्तमान में जर्मनी में लगभग 36 हजार से 39 हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जो मुख्य रूप से स्टुटगार्ट और रामस्टाइन जैसे प्रमुख सैन्य ठिकानों पर तैनात हैं। ट्रंप के इस फैसले के समय की तुलना में यह संख्या पहले ही काफी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी यह यूरोप की सुरक्षा संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। इस बयान को कई विशेषज्ञ एक रणनीतिक दबाव के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका पहले ही सैन्य तैनाती को राजनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। हालांकि जर्मनी ने इस स्थिति को संभालने की कोशिश की। जर्मन विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी सैनिकों को तैनाती में बदलाव कोई नई बात नहीं है और यह पहले ही विभिन्न अमेरिकी प्रशासन के दौरान चर्चा का विषय रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जर्मनी इस तरह

के संभावित बदलावों के लिए तैयार है और NATO के ढांचे के भीतर अमेरिका के साथ सशक्त जारी रखेगा। दूसरी ओर, मर्ज़ ने भी बाद में अपने रुख को थोड़ा नरम करते हुए अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया और यह स्पष्ट किया कि जर्मनी ट्रांस-अटलांटिक संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस पूरे घटनाक्रम को केवल व्यक्तिगत बयानबाजी के रूप में देखना एक बड़ी भूल होगी। इसके पीछे गहरे रणनीतिक मतभेद छिपे हैं। अमेरिका जहां अपनी “America First” नीति के तहत यूरोप से अधिक आत्मनिर्भरता की अपेक्षा करता है, वहीं जर्मनी और अन्य यूरोपीय देश एक संतुलित नीति अपनाना चाहते हैं, जिसमें कूटनीति और बहुपक्षीय सहयोग को प्राथमिकता दी जाए। Iran के कट्टर पर अमेरिका सख्त रुख अपनाता है, जबकि जर्मनी वार्ता के जरिए समाधान चाहता है। इसी तरह Russia और Ukraine के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी दोनों देशों के दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह विवाद यूरोप की रणनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ते कदमों का संकेत भी हो सकता है। जर्मनी धीरे-धीरे अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह अभी भी अमेरिकी सैन्य और खुफिया सहयोग पर काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में यह टकराव दोनों देशों के लिए एक परीक्षा बन गया है, जहां उन्हें अपने हितों और साझेदारी के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक ट्रंप और मर्ज़ के संबंध काफी अच्छे माने जाते थे। व्लाड्ट हाउस में हुई एक मुलाकात के दौरान ट्रंप ने मर्ज़ को मित्र बताया था और उनके काम की सराहना भी की थी। लेकिन हालिया घटनाओं ने इस तनाव पर सवाल खड़ा कर दिए हैं और यह दिखाया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में रिश्ते कितनी तेजी से बदल सकते हैं। यूरोप के अन्य नेताओं के साथ भी ट्रंप के संबंधों में तनाव देखा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल जर्मनी तक सीमित मुद्दा नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर अमेरिका के सैन्य नीतियों का प्रभाव है। आने वाले समय में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह टकराव और गहराता है या फिर कूटनीति के जरिए दोनों देश अपने मतभेदों को सुलझाने में सफल होते हैं। फिलहाल इतना तय है कि ट्रंप और मर्ज़ के बीच यह विवाद केवल शब्दों की जंग नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत है, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस-सूरत में 3.53 लाख करोड़ रुपए के 2,792 एमओयू हुए : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

► **उप मुख्यमंत्री का उद्योगकारों तथा निवेशकों को आश्वासन : प्रगतिशील विचारधारा के साथ आगे बढ़ें, सरकार आपको विश्वभर के बायर्स तक पहुँचाने तथा आवश्यक व्यवस्था प्रदान करने में संपूर्ण सहायता करेगी**

► **वीजीआरसी का समापन, परंतु 5 मई तक आयोजित एग्जीबिशन देखने का उप मुख्यमंत्री का अनुरोध**

► **दक्षिण गुजरात के विभिन्न कैटेगरी में श्रेष्ठ एमएसई तथा एमएसएमई अवॉर्ड प्रदान, हस्तकला कारीगरों का सम्मान**

(जीएनएस)। गांधीनगर : सूरत के आंग्रे विश्वविद्यालय में 1 एवं 2 मई के दौरान आयोजित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस-दक्षिण गुजरात का शनिवार को समापन हुआ। उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3,53,306 लाख करोड़ रुपए के 2,792 एमओयू होने की घोषणा की। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने समापन सत्र में कहा कि इस कॉन्फ्रेंस द्वारा दक्षिण गुजरात के विकास के लिए जो नींव रखी गई है, उससे यह परिक्षेत्र आगामी समय में बड़ी आर्थिक छलांग लगाने को तैयार हुआ है। उन्होंने गुजरात की आर्थिक शक्ति की सहायता करते हुए कहा कि गुजरात का देश की कुल जीडीपी में 8 प्रतिशत, मैन्युफैक्चरिंग में 17 प्रतिशत, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 27 प्रतिशत तथा कारगो हैंडलिंग में 40 प्रतिशत हिस्सा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने आर्थिक प्रगति ही नहीं की,

‘नारी वंदन’ पर सियासी टकराव: गुजरात बयान से गरमाई राजनीति, राहुल-प्रियंका का बीजेपी पर तीखा हमला

(जीएनएस)। नई दिल्ली/अहमदाबाद। देश की राजनीति में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। गुजरात से उठे एक विवादित बयान ने राष्ट्रीय स्तर पर सियासी बहस को तेज कर दिया है, जहां Rahul Gandhi ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए उसे “महिला-विरोधी मानसिकता” का प्रतीक बताया है। मामला गुजरात भाजपा अध्यक्ष Jagdish Vishwakarma की उस टिप्पणी से जुड़ा है, जो उन्होंने कांग्रेस सांसद Geniben Thakor को लेकर एक जनसभा में दी थी। इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं और यह विवाद अब राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन गया है। राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा के “नारी वंदन” जैसे नारों के विपरीत बताते हुए कहा कि यह केवल दिखावा है, जबकि वास्तविकता में पार्टी के भीतर महिलाओं के प्रति सम्मान का अभाव नजर आता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गुजरात भाजपा अध्यक्ष की टिप्पणी न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह उस सोच को उजागर करती है, जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के बजाय उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करती है। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि सत्ता को चुनौती देने वाली महिलाओं को भाजपा बदराश नहीं कर पाती और जैसे ही कोई महिला नेता मजबूत तरीके से सामने आती है, उसके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर वे महिलाओं के सम्मान की बात करते



हैं, लेकिन दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता इस तरह के बयान देकर उस संदेश को कमजोर करते हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि संसद में महिला सांसदों के सवालों से बचने की प्रवृत्ति भी इसी मानसिकता को दर्शाती है। उनके अनुसार, यह विरोधाभास भाजपा की नीतियों और उसके नेताओं के व्यवहार के बीच स्पष्ट अंतर को उजागर करता है। इस विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब गुजरात भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने एक जनसभा में कांग्रेस सांसद गीनोबेन ठाकरे को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी “साड़ी के पल्लू में बंधी पंचायत सीटें खींच ली गई हैं।” इस बयान को कांग्रेस ने बेहद अपमानजनक और असंवेदनशील बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस तरह की भाषा न केवल एक महिला सांसद का अपमान है, बल्कि यह समाज में महिलाओं के प्रति गलत संदेश भी देती है। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह पार्टी के भीतर महिलाओं के प्रति नजरिए को दर्शाता है। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि भाजपा में ऐसे बयानों को रोकने के बजाय उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। कांग्रेस



मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत कर उद्योगपतियों के साथ संवाद एवं सहयोग की जो संस्कृति विकसित की, वह आज देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय मॉडल बनी है। ऐसे प्रयासों के कारण ही आज भारत विश्व में निवेश के लिए सबसे विश्वसनीय स्थान बना है। दक्षिण गुजरात में सेक्टरल स्ट्रैथ की भूमिका देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सूरत के डायमंड एवं टेक्सटाइल उद्योग से लेकर भरूच-दहेज-अंकलेश्वर के केमिकल तथा फर्टिलाइजर उद्योग वैश्विक हब बने हैं। अब टेक्सटाइल के साथ गारमेंटिंग उद्योग को जोड़कर

विकास के नए द्वार खोले जा रहे हैं, जो स्थानीय क्षेत्र तथा राज्य सरकार की बड़ी जीत मानी जाएगा। वैश्विक अनिश्चितताओं के समय में आत्मनिर्भर बनने तथा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि आपदा को अवसर में बदलकर गुजरात जिस प्रकार स्ट्रेच्यू ऑफ यूनिटी, गिफ्ट सिटी तथा हाईस्पीड रेल जैसे प्रोजेक्ट्स द्वारा आगे बढ़ रहा है, वह विकासित भारत के संकल्प को साकार करने में आधारभूत बनेगा। उन्होंने वीजीआरसी के आयोजन के लिए राज्य सरकार को अभिन्नंदन दिया। उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस दक्षिण गुजरात की क्षमता को देश एवं दुनिया के समक्ष उजागर करने वाला महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनी है। दक्षिण गुजरात के

औद्योगिक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास तथा रोजगार सृजन के लिए यह दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक सिद्ध हुई है। आगामी तीन वर्ष में एमओयू के अनुसार प्रोजेक्ट्स कार्यरत होने से दक्षिण गुजरात के 2.82 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। श्री संघवी ने गौरवपूर्वक कहा कि वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात की औद्योगिक शक्ति को विश्व के समक्ष रखने के लिए वाइब्रेंट गुजरात का जो विचार प्रवाहित किया था, उसके फलस्वरूप राज्य की जीडीपी 1.29 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर आज 27.09 लाख करोड़ रुपए तक पहुँची है। पिछले 24 वर्ष की इस दृढ़ विकास यात्रा में टीम गुजरात तथा राज्य के व्यापारी अनेक मुश्किलों के

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे. पी. नड्डा

► गुजरात देश का ग्लोबली कनेक्टेड इंजन, वाइब्रेंट रीजनल कॉन्फ्रेंस से दक्षिण गुजरात के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी

► आपदा को अवसर में बदलकर आत्मनिर्भरता की व्याख्या गुजरात ने देश को दी, सूरत-भरूच मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देशभर में उभरे

बावजूद पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने जोड़ा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल प्रथम पंक्ति के उद्योगपतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतिम पंक्ति में बैठे छोटे व्यापारियों के सपने साकार करने की है। राज्य सरकार इस दिशा में कार्यरत है कि वाइब्रेंट रीजनल कॉन्फ्रेंस का सीधा लाभ छोटे उद्यमियों को मिले। उप मुख्यमंत्री ने एक नूतन पहल करते हुए घोषणा की कि अब से रीजनल कॉन्फ्रेंस केवल नए निवेशकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। उन्होंने अनुरोध किया कि वीजीआरसी का समापन हुआ है, लेकिन 5 मई तक आयोजित एग्जीबिशन देखने के लिए अधिक से अधिक उद्यमी युवा तथा नागरिक आएँ। गुजरात प्रदेश संगठन अध्यक्ष श्री जगदीशभाई विश्वकर्मा ने कहा कि 2003 से शुरू हुई वाइब्रेंट समिट की यह यात्रा आज 2026 में टैलेंट, टेक्नोलॉजी तथा ट्रांसपरेसी की पर्याय बनी है। गुजरात के लिए ओपन डोर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जहाँ सरकार के जिम्मेदार अधिकारी उद्योगकारों से सीधा संवाद करेंगे। उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने की नीति पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इंसेंटिव क्लियरेंस की प्रक्रिया में निरंतर गति ला रही है। पूर्व में प्रतिदिन

सूरत में ‘गौ सम्मान’ के लिए महाअभियान: व्यापारियों की रणनीति बैठक, 7 मई की रैली को लेकर व्यापक तैयारी

(जीएनएस)। सूरत। शहर में ‘गौ सम्मान अभियान’ अब एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है, जहां व्यापारिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की व्यापक भागीदारी इस पहल को नई दिशा दे रही है। मिलेनियम मार्केट स्थित फोस्टा बोर्ड रूम में आयोजित रणनीतिक बैठक ने इस अभियान को संगठित रूप देने का काम किया, जिसमें 7 मई को प्रस्तावित विशाल रैली को लेकर विस्तृत योजना बनाई गई। बैठक में उपस्थित लोगों का उद्देश्य और एकजुटता इस बात का संकेत दे रही थी कि यह कार्यक्रम केवल एक रैली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहरव्यापी जागरूकता का केंद्र बनेगा। बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल एक दिन की गतिविधि नहीं, बल्कि समाज में गौ संरक्षण और सम्मान के प्रति दीर्घकालिक सोच विकसित करना है। व्यापारियों ने यह महसूस किया कि यदि किसी सामाजिक मुद्दे को व्यापक समर्थन देना है, तो उसे जमीनी स्तर तक पहुंचाना जरूरी है। इसी सोच के तहत रैली की रूपरेखा इस तरह तैयार की गई है कि शहर के अधिकतम क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अमरोली, वराछा, कतारगांव, रिंग रोड, पर्वत पाटिया, ऊन, नंदेश्वर गौशाला और माधव गौशाला जैसे क्षेत्रों से अलग-अलग समूह सुबह 9 बजे मिलेनियम मार्केट के सामने एकत्रित होंगे। यह जापन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि इस अभियान के संदेश को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का एक माध्यम होगा। बैठक में आध्यात्मिक वक्ता Sadhvi Kapila Didi की उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने अपने संबोधन में अभियान के उद्देश्यों को विस्तार से समझाया और सभी उपस्थित लोगों को यह संदेश दिया शहर को जोड़ने का प्रयास कर रहा है।



सुबह 9:30 बजे रैली की शुरुआत होगी, जो मिलेनियम मार्केट से निकलकर विनता विश्राम पहुंचेगी। इस मार्ग को इसलिए चुना गया है ताकि शहर के प्रमुख इलाकों को जोड़ा जा सके और अधिक से अधिक लोग को इसमें शामिल हो सकें। विनता विश्राम पर भटार, वेसु, पांडेसरा, सिटीलाइट और अडाजन जैसे क्षेत्रों से आने वाले समूह भी रैली में शामिल होंगे, जिससे इसकी संख्या और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय की मार्च करेंगे और वहां राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नाम जापन सौंपेंगे। यह जापन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि इस अभियान के संदेश को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का एक माध्यम होगा। बैठक में आध्यात्मिक वक्ता Sadhvi Kapila Didi की उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने अपने संबोधन में अभियान के उद्देश्यों को विस्तार से समझाया और सभी उपस्थित लोगों को यह संदेश दिया कि यह केवल धार्मिक भावना से

199 आवेदन क्लियर होते थे, जो अब दुगुने हो गए हैं और आगामी समय में यह आँकड़ा 500 के पार जाएगा। इससे पूर्व प्रारंभ में उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव श्री ममता वर्मा ने स्वागत संबोधन में रीजनल कॉन्फ्रेंस को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके कारण आदिजाति क्षेत्र की 25 हजार से अधिक महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री संघवी ने उद्योगकारों-निवेशकों को आश्वासन दिया कि प्रातिशील विचारधारा के साथ आगे बढ़ें, सरकार आपको विश्वभर के बायर्स तक पहुँचाने तथा सभी व्यवस्था प्रदान करने में संपूर्ण सहायता करेगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न सेक्टर में हुई गहन चर्चाओं तथा मंथन उद्योगकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। उन्होंने अनुरोध किया कि वीजीआरसी का समापन हुआ है, लेकिन 5 मई तक आयोजित एग्जीबिशन देखने के लिए अधिक से अधिक उद्यमी युवा तथा नागरिक आएँ। गुजरात प्रदेश संगठन अध्यक्ष श्री जगदीशभाई विश्वकर्मा ने कहा कि 2003 से शुरू हुई वाइब्रेंट समिट की यह यात्रा आज 2026 में टैलेंट, टेक्नोलॉजी तथा ट्रांसपरेसी की पर्याय बनी है। गुजरात के समूह एवं रचनात्मक विकास में वाइब्रेंट समिट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज ग्रोथ उत्तरोत्तर बढ़ा है। आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया की छवि गुजरात में ही नहीं, बल्कि देश-विदेश में स्थापित हुई है। व्यापार-धंधे के लिए विश्वसनीय स्थल के रूप में

गुजरात उभर रहा है। गुजरात में इंडस्ट्रीज फ्रेंडली वातावरण है, जिसके कारण निवेश के लिए गुजरात बेस्ट डेस्टिनेशन बना है। इससे पूर्व प्रारंभ में उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव श्री ममता वर्मा ने स्वागत संबोधन में रीजनल कॉन्फ्रेंस को फलदायी बताते हुए कहा कि पिछले दो दिन में स्केल एवं स्किल के समन्वय के साथ उद्यमियों को मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। दक्षिण गुजरात के उद्योगकारों तथा युवा उद्यमियों को मजबूत मंच प्रदान करने का सफल प्रयास हुआ। यहाँ बीटूडी, बीटूडी, रिवर्स पायर्स सेलर्स मीट तथा थ्रूखलाबड सेमिनारों से युवा पीढ़ी को नई दिशा मिली है। इस अवसर पर मंत्रियों तथा महानुभावों के करकमलों से विभिन्न कैटेगरी में श्रेष्ठ एमएसई तथा एमएसएमई अवॉर्ड प्रदान किए गए। इसके अलावा; हस्तकला कारीगरों का पुरस्कार के साथ सम्मान किया गया। आंग्रे विश्वविद्यालय के संचालकों का आभार के साथ सम्मान किया गया। महानुभावों ने दक्षिण गुजरात की औद्योगिक क्षमता तथा वीजीआरसी के विजन को प्रस्तुत करने वाले विशेष सेवोनिष्प का अनावरण किया। समापन समारोह में कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, जलपूर्ति मंत्री श्री कुँवरजीभाई बावळिया, आंग्रे विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री हसमुख रामा, अग्रणी लैबप्रोन उद्योगकार स्मित पटेल, व्यापार-उद्योग जगत के प्रतिनिधि, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, उच्चाधिकारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

आजी डैम बना नामा मतम का सागरः पिता-पुत्र समेत चार लोग डूबे, एक की तलाश जारी

(जीएनएस)। राजकोट। गुजरात के राजकोट में स्थित Aji Dam पर शनिवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। एक ही परिवार से जुड़े चार लोगों के डूबने की घटना ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को झकझोर दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि थोड़ी सी लापरवाही कैसे बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। इस हादसे में पिता-पुत्र समेत तीन लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति की तलाश अब भी जारी है। बचाव दल लगातार सच ऑपरेशन में जुटा हुआ है, लेकिन समय बोलने के साथ उम्मीदें कमजोर होती जा रही हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, राजकोट के घांचीवाड़ इलाके में रहने वाले भरत जयराव अपने परिवार के साथ सप्ताहांत पर धार्मिक स्थल Mogal Mataji Temple में दर्शन करने पहुंचे थे। उनके साथ उनके दो बेटे और साली का बेटा भी था। परिवार ने मंदिर में पूजा-अर्चना की और उसके बाद डैम के आसपास कुछ समय बिताने लगे। यह एक सामान्य परिवारिक सैर की तरह शुरू हुआ दिन था, जो कुछ ही पलों में भयावह हादसे में बदल गया। बताया जा रहा है कि समूह में से एक युवक अचानक संतुलन खो बैठा और डैम के गहरे पानी में गिर गया। उसे डूबता देख अन्य लोग बिना देर किए उसे बचाने के लिए पानी में उतर गए। लेकिन जिस पानी को बरामद कर लिए गए थे, वह अंदर से बेहद गहरा और खतरनाक था। एक के बाद एक चारों लोग पानी में समा गए और बाहर नहीं निकल सके। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने शोध मचाया और तुरंत पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। बचाव कार्य के लिए गोताखोरों को बुलाया गया और सच ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी मशकत के बाद तीन लोगों—भरत जादव, उनके बेटे धवल

जादव और ध्रुव मकवाना—के शव बरामद किए जा सके। चौथे व्यक्ति की तलाश अब भी जारी है, जिसके लिए डैम के आसपास का पूरा क्षेत्र खंगाला जा रहा है। इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जलाशयों और डैम जैसे स्थानों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं होते। अक्सर देखा गया है कि लोग इन जगहों को पिकनिक स्पॉट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां गहराई, फिसलन और तेज धार जैसे खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार चेतावनी बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, जिसका परिणाम ऐसे दर्दनाक हादसों के रूप में सामने आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आजी डैम के आसपास पहले जलोट-मोटे हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस तरह की बड़ी त्रासदी ने सभी को हिला कर रख दिया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

सूरत-उधना में यात्रियों का दबाव बढ़ा : प्रमुख ट्रेनों को साप्ताहिक से दैनिक करने की मांग तेज

(जीएनएस)। सूरत। दक्षिण गुजरात के औद्योगिक हब सूरत और उधना रेलवे स्टेशनों पर लगातार बढ़ती भीड़ अब एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पिछले दो वर्षों में यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके चलते ट्रेन सेवाओं पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार विकास मंडल ने महत्वपूर्ण ट्रेनों को साप्ताहिक के बजाय प्रतिदिन संचालित करने की मांग उठाई है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके और भीड़भाड़ की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके। मंडल के अध्यक्ष प्रभुनाथ यादव, महासचिव बांके बिहारी सिंह और अन्य पदाधिकारियों ने सांसद Mukesh Dalal के माध्यम से रेल मंत्री को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में विशेष रूप से Shramik Express 19051 और Surat Muzaffarpur Express 19053 को दैनिक चलाने की मांग की गई है। इसके अलावा Avadh Express 19037 में सूरत से आरक्षण कोटा और आपातकालीन कोटा बढ़ाने की भी आवश्यकता जताई गई है।



मंडल का कहना है कि दक्षिण गुजरात के सूरत, कोम, अंकलेश्वर, भरूच, वलसाड और वापी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और बिहार के करीब 20 लाख से अधिक श्रमिक और व्यापारी काम करते हैं। ये लोग रोजगार के लिए यहां बसे हुए हैं, लेकिन त्योहारों और पारिवारिक अवसरों पर बड़ी संख्या में अपने गृह राज्यों की ओर जाते हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, होली, रामनवमी और विवाह सीजन के दौरान यह संख्या और बढ़ जाती है, जिससे रेलवे

सूरत-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के रूट को लखनऊ के बाद बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और कप्तानगंज होते हुए या वैकल्पिक रूप से बेतिया और मोतिहारी के जरिए मुजफ्फरपुर तक विस्तारित करने की मांग की गई है। इस विस्तार और आवृत्ति बढ़ाने से न केवल यात्रियों की सुविधा में सुधार होगा, बल्कि अनारक्षित डिब्बों में होने वाली भीड़भाड़ और असुविधा भी कम हो सकती है। वर्तमान में कई यात्री मजबूरी में वैटिंग टिकट या जनरल कोच में यात्रा करते हैं, जिससे सुरक्षा और आराम दोनों प्रभावित होते हैं। मंडल ने अपने प्रस्ताव में रूट विस्तार का भी सुझाव दिया है, जिससे अधिक क्षेत्रों को सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। 19051 श्रमिक एक्सप्रेस, जो वर्तमान में वलसाड से मुजफ्फरपुर तक सप्ताह में एक बार चलती है, उसे वाराणसी के बाद औडिहार, मऊ, सलेमपुर, भटनी और सिवान के रास्ते आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी तरह 19053

श्रमिकों का स्रोत है, जो रोजगार के लिए सूरत और आसपास के औद्योगिक इलाकों में आते हैं। बेहतर रेल सुविधा मिलने से उनके आवागमन में आसानी होगी और समय की बचत भी होगी। सांसद Mukesh Dalal ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ ध्यान देंगे। उनका कहना है कि यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए रेलवे को अपनी सेवाओं में सुधार करना आवश्यक है और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। कुल मिलाकर, सूरत और उधना रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा रेल सेवाएं अब पर्याप्त नहीं रह गई हैं। ऐसे में ट्रेनों को दैनिक चलाने और रूट विस्तार जैसे कदम न केवल समय की जरूरत हैं, बल्कि लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए भी बेहद जरूरी हैं। अब देखा जा रहा है कि रेलवे प्रशासन इस मांग पर कितना जल्दी और प्रभावी निर्णय लेता है, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके।